आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
रविवार 12.10.2025
समय 07.20

मुख्य समाचार :–

- प्रदेश सरकार दुर्गम क्षेत्रों में तैनात वन कर्मियों को आवासीय भत्ता देगी।
- राज्यभर में कफ सिरप की बिक्री पर सख्त निगरानी; 350 से अधिक नमूने जांच के लिए भेजे गए; एक दर्जन से अधिक मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निरस्त।
- प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढामुक्त करने का काम जारी, 52 प्रतिशत पैच वर्क पूरा; मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी कार्य शीघ्रता से पूरा करने के निर्देश दिए।
- राज्य की 326 मेधावी बेटियों को अंतर्राष्ट्रीय बालिक दिवस पर स्मार्टफोन प्रदान किए गए।

निर्णय

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत वन कर्मियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। अब ऐसे वन कर्मियों को आवासीय भत्ता दिया जाएगा, जो कठिन परिस्थितियों में राज्य की वन संपदा और वन्यजीवों की सुरक्षा में तैनात हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्गम चौकियों पर कार्य करने वाले वन कर्मियों को अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है, जिससे उनके लिए आवास व्यवस्था एक बड़ी चुनौती बन जाती है। सरकार ने इस कठिनाई को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया है कि जिन क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, वहां तैनात वन कर्मियों को आवासीय भत्ता अनुमन्य किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि यह निर्णय उन कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आएगा जो जंगलों की सुरक्षा में निरंतर कार्यरत हैं। वित्त विभाग की सहमति से ऐसे दुर्गम क्षेत्रों की पहचान की जाएगी जहां यह सुविधा लागू होगी। वन विभाग के कर्मचारियों ने इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वन मंत्री सुबोध उनियाल का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इस कदम से उन्हें अपने परिवारों की देखभाल में सुविधा मिलेगी और वे राज्य की वन संपदा की सुरक्षा में और अधिक समर्पण के साथ कार्य कर सकेंगे।

पीएम संबोधन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री धन–धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन जैसी योजनाएँ देश के लाखों किसानों का भाग्य बदल देंगी। श्री मोदी ने कहा कि इन योजनाओं से आत्मनिर्भरता, ग्रामीण सशक्तिकरण और कृषि नवाचार के नए अध्याय की शुरुआत होगी।

प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कल 42 हज़ार करोड़ रुपये से अधिक की कई परियोजनाओं और योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने आत्मनिर्भरता के लिए देश की कृषि प्रणाली में तेज़ी से विकास और सुधारों को आवश्यक बताया।

एनडीए शासन की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले ग्यारह वर्ष में देश का कृषि निर्यात लगभग दोगुना हो गया है और अनाज उत्पादन में करीब 90 मिलियन मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है।

मेडिकल स्टोर्स लाइसेंस रद्द

बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते औषधि विभाग, राज्यभर में कफ सिरप की बिक्री पर सख्त निगरानी रख रहा है। अब तक 350 से अधिक नमूने जांच के लिए गए हैं, जबकि एक दर्जन से अधिक मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं।

देहरादून में औषधि विभाग की टीम ने पलटन बाजार, घंटाघर, ऋषिकेश रोड, जॉलीग्रांट, अजबपुर और नेहरू कॉलोनी क्षेत्रों में मेडिकल स्टोर्स की जांच की। कुछ स्थानों पर बच्चों की सर्दी–खांसी की दवाएं अलग से भंडारित पाई गईं, जिन्हें सील कर दिया गया। एक मेडिकल स्टोर को बंद किया गया और 11 औषधियों के नमूने जांच के लिए लिए गए।

ऋषिकेश में औषधि निरीक्षक निधि रतूड़ी की टीम ने छह औषधियों के नमूने लिए और जिन स्टोर्स में बच्चों की दवाएं पाई गईं, वहां स्टॉक सील किया गया। हल्द्वानी में सात मेडिकल स्टोर्स की जांच की गई और दो सिरप के नमूने जांच के लिए लिए गए। अल्मोड़ा और बागेश्वर में भी निरीक्षण कर कुल तीन सिरप के नमूने परीक्षण के लिए भेजे गए।

अपर आयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रशासन– एफडीए, ताजबर सिंह जग्गी ने कहा कि यह अभियान चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा और सरकार का लक्ष्य है कि राज्य में केवल सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण दवाएं ही उपलब्ध हों।

पैच वर्क– मुख्यमंत्री निर्देश

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की सभी सड़कों को जल्द से जल्द गड्ढामुक्त करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में निर्माण और पुनर्निर्माण कार्यों को प्राथमिकता दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक आधारभूत संरचनाओं और क्षतिग्रस्त पुलों का जल्द निर्माण किया जाए, ताकि स्थानीय लोगों को राहत मिल सके।

बैठक में बताया गया कि सड़कों को गड्ढामुक्त करने की दिशा में अब तक 52 प्रतिशत पैच वर्क का कार्य पूरा किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने शेष कार्यों को त्वरित गति से पूरा करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के प्रभारी सचिव से अपने–अपने जिलों का नियमित भ्रमण कर जनता से संवाद स्थापित करने और विकास तथा जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने को भी कहा। उन्होंने अधिकारियों को कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और कहा कि राज्य सरकार जनता को सुरक्षित और सुविधाजनक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

स्मार्टफोन वितरण

देहरादून में अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 326 मेधावी बालिकाओं को स्मार्टफोन प्रदान किए गए।

मुख्यमंत्री ने जिला स्तर पर हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा की प्रथम तीन टॉपर बालिकाओं तथा विकासखंड स्तर की टॉपर बालिकाओं को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि समाज की तरक्की नारी शक्ति से होती है। राज्य सरकार ने महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण देने के साथ मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना, महालक्ष्मी योजना, वात्सल्य योजना और नंदा गौरा योजना जैसी योजनाएं शुरू की हैं, जिनसे प्रदेश की बेटियाँ आत्मनिर्भर बन रही हैं।

इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य में महिला सशक्तिकरण को नई गति मिली है। बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ अभियान के बाद राज्य में बेटियों के लिंगानुपात में सुधार हुआ है।

गुलदार प्रभावित गांवों में पिंजरे

कैबिनेट मंत्री और चौबट्टाखाल विधायक सतपाल महाराज ने पौड़ी जिले के एकेश्वर और पोखड़ा ब्लॉक के गुलदार प्रभावित गांवों में पिंजरे लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिलाधिकारी पौड़ी और वन विभाग के अधिकारियों से बात कर डयूला, देवकुंडई और आसपास के इलाकों में तत्काल पर्याप्त संख्या में पिंजरे लगाने को कहा।

महाराज ने बताया कि वन विभाग स्थिति पर पूरी तरह नजर रखे हुए है। गुलदार को ट्रेंकुलाइज करने के लिए वन कर्मियों को ट्रेंकुलाइजर गन दी गई हैं, गश्त बढ़ा दी गई है और गतिविधियों की निगरानी के लिए कैमरे लगाए जा रहे हैं। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।

डाक लिफ़ाफे जारी

नैनीताल के कुमाऊं विश्वविद्यालय और आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान (एरीज) के लिए शनिवार का दिन ऐतिहासिक रहा, जब भारतीय डाक विभाग ने दोनों संस्थानों की शैक्षणिक उत्कृष्टता और सामाजिक योगदान के सम्मान में उनके चित्रों वाले विशेष स्मारक डाक लिफाफे जारी किए।

राज्य अतिथि गृह नैनीताल क्लब में आयोजित नैनी पैक्स कार्यक्रम में लिफाफे जारी किए गए।

सड़क परिवहन, राजमार्ग एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि ये स्मारक लिफाफे कुमाऊं विश्वविद्यालय और एरीज की शैक्षणिक परंपरा, सांस्कृतिक विरासत और समाज के प्रति योगदान के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि ये दोनों संस्थान उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश के लिए ज्ञान और अनुसंधान के केंद्र हैं।

समीक्षा

सचिव उत्तराखंड शासन दिलीप जावलकर ने कल अल्मोड़ा स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में जिले में संचालित विभिन्न विभागीय योजनाओं, कार्यक्रमों और बेस्ट प्रैक्टिस की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों से आपदा प्रबंधन, सिंचाई, जलागम विकास और राजस्व विभाग की प्रगति की विस्तृत जानकारी ली।

सचिव ने निर्देश दिए कि सभी योजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से किया जाए ताकि जनता को अधिकतम लाभ मिल सके। उन्होंने विशेष रूप से जलागम प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि कार्यों को तेजी से पूरा किया जाए और इन्हें ग्राम पंचायत विकास योजना में शामिल किया जाए। साथ ही सभी जलागम कार्यों में वनीकरण को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि जल संरक्षण और भूमिगत जल के पुनर्भरण में वनीकरण का महत्वपूर्ण योगदान है। सिंचाई और जलागम परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों से नवीन तकनीकों के उपयोग पर बल दिया।

सचिव जावलकर ने कहा कि जनपद के विकास के लिए शासन स्तर से हरसंभव सहयोग किया जाएगा। उन्होंने जिलाधिकारी को लंबित कार्यों और आवश्यक मदद से संबंधित विवरण शासन को भेजने के निर्देश दिए ताकि उनका शीघ्र निस्तारण हो सके।